देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 06.12.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- केंद्र सरकार ने चम्पावत के टनकपुर से महाराष्ट्र स्थित तख्त श्री नांदेड़ साहिब तक नई रेल सेवा की शुरुआत को मंजूरी दी।
- राज्य सरकार ने पेराई सत्र 2025–26 के लिए गन्ना मूल्य वृद्धि का शासनादेश जारी किया; अगेती प्रजाति का मूल्य 405 रुपये प्रति कुंतल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 395 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग की सभी पेंशन हर माह की 5 तारीख तक लाभार्थियों के खातों में पहुंचाने के निर्देश दिए।
- राज्य में एस०आई०आर की तैयारियां शुरू; प्री–एस०आई०आर चरण में 2003 की सूची वाले 40 वर्ष तक के मतदाताओं की बी.एल.ओ ऐप से होगी मैपिंग।

नई रेल सेवा

चम्पावत के टनकपुर से महाराष्ट्र स्थित तख्त श्री नांदेड़ साहिब तक नई रेल सेवा की शुरुआत को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे नांदेड़ साहिब की यात्रा उत्तराखंड के श्रद्धालुओं के लिए आसान और सुविधाजनक होगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह रेल सेवा तराई क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए लाभदायक होगी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी।

इस सेवा से प्रदेश की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और व्यापार, पर्यटन व सांस्कृतिक यात्राओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

गन्ना समर्थन मूल्य बढोतरी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति के बाद पेराई सत्र 2025–26 के लिए गन्ना मूल्य वृद्धि का शासनादेश जारी कर दिया गया है। नई दरों के अनुसार अगेती प्रजाति का मूल्य 405 रुपये प्रति कुंतल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 395 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है।

पिछले पेराई सत्र में अगेती प्रजाति का मूल्य 375 रुपये और सामान्य प्रजाति का मूल्य 365 रुपये था। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ा हुआ मूल्य किसानों को लाभ देगा और कृषि अर्थव्यवस्था

को मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और क्रय केंद्रों पर किसी प्रकार की परेशानी न होने के निर्देश दिए।

नए आदेश के अनुसार बाह्य क्रय केंद्रों से गन्ने के परिवहन में 11 रुपये प्रति कुंतल की कटौती लागू होगी। तय दरों के आधार पर भुगतान कराना सभी चीनी मिलों के लिए अनिवार्य किया गया है और भुगतान की जानकारी मासिक रूप से शासन को भेजी जाएगी।

समिति गठन

केंद्र सरकार ने इंडिगो की उड़ानों के परिचालन में बाधा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों की व्यापक समीक्षा के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति 15 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा कि समिति व्यापक परिचालन बाधाओं के मूल कारणों की पहचान करेगी। इनमें उड़ान ड्यूटी समय सीमा के कार्यान्वयन की तैयारियों का आकलन शामिल है। समिति परिचालन स्थिरता में व्यवधान उत्पन्न करने वाली नियोजन विफलताओं के लिए जवाबदेही और उत्तरदायित्व तय करेगी। यह एयरलाइन उड़ान संचालन की बहाली के लिए पर्याप्त कदम उठाने के बारे में आकलन करेगी।

नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि इंडिगो की उड़ानों में देरी और रद्दीकरण की स्थिति में सुधार हो रहा है। उन्होंने उडानों के समय पर परिचालन की आशा व्यक्त की है। इस बीच, नागर विमानन महानिदेशालय के उड़ान ड्यूटी समय सीमा संबंधी आदेश तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिए गए हैं।

विनियमितीकरण नियमावली–2025

राज्य सरकार ने विनियमितीकरण नियमावली–2013 में संशोधन करते हुए दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों के लिए नई विनियमितीकरण नियमावली–2025 जारी कर दी है।

सचिव कार्मिक शैलेश बगोली द्वारा अधिसूचना के अनुसार, 04 दिसंबर 2018 तक संबंधित पद पर या समकक्ष पद पर कम से कम 10 वर्ष की निरंतर सेवा देने वाले कर्मचारी विनियमितीकरण के पात्र होंगे, बशर्ते वे अन्य शर्तें भी पूरी करते हों।

पूर्व में 2013 की नियमावली के अनुसार, नियम लागू होने की तिथि तक कम से कम 5 वर्ष की सेवा करने वाले कर्मचारी पात्र माने जाते थे।

मुलाकात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में परिवीक्षाधीन पीसीएस अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रशासनिक सेवा केवल नौकरी नहीं, बल्कि जनता की सेवा का दायित्व है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा का उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। उन्होंने युवा अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे संवेदनशील और नवाचारी सोच के साथ प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाएंगे, ताकि जनता को तेज और प्रभावी सेवाएं मिल सकें।

श्री धामी ने सलाह दी कि अधिकारी, जनता की समस्याओं को मानवीय दृष्टिकोण से समझते हुए समाधान–केन्द्रित तरीके से कार्य करें। उन्होंने कहा कि ईमानदारी, निष्पक्षता और न्याय एक अधिकारी की पहचान होती है।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की भौगोलिक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में सेवाएं पहुंचाना कठिन होता है, इसलिए अधिकारियों को अतिरिक्त मेहनत और संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि अधिकारी सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को प्राथमिकता देंगे।

पेंशन हस्तांतरण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग की सभी पेंशन हर माह की 5 तारीख तक लाभार्थियों के खातों में पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पेंशन भुगतान में किसी भी तरह की देरी स्वीकार नहीं होगी। श्री धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नवंबर 2025 की लगभग एक सौ चालीस करोड़ रुपए की पेंशन किश्त जारी की, जिससे करीब 9 लाख 39 हजार लाभार्थियों को लाभ मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभाग को पेंशन प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने पेंशन योजनाओं का नियमित आंतरिक ऑडिट करने को कहा, ताकि अयोग्य व्यक्ति लाभ प्राप्त न कर सकें। समान प्रकृति की योजनाओं को एकीकृत कर डुप्लीकेसी समाप्त करने के भी निर्देश दिए।

एस०आई०आर की तैयारियां

राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण–एस०आई०आर के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि प्री–एस०आई०आर चरण में प्रदेश की मतदाता सूची में शामिल 40 वर्ष तक के उन मतदाताओं की बीएलओ ऐप के माध्यम से मैपिंग की जाएगी, जिनके नाम 2003 की सूची में दर्ज थे।

सचिवालय में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बूथ लेवल एजेंट्स और बूथ लेवल अधिकारियों के समन्वय से यह प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी होगी। बैठक में 31 दिसंबर तक प्रत्येक बूथ पर बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने की अपील की गई। प्रदेश में वर्तमान में 11 हजार 733 बूथों के मुकाबले 4 हजार 155 बीएलए ही नियुक्त हैं।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए सभी दलों को अपने बूथ लेवल एजेंट 31 दिसंबर तक नियुक्त कर देने चाहिए।

दीक्षांत समारोह

देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी– आई.एम.ए के आर्मी कैडेट कॉलेज विंग में दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें तीन वर्ष के शैक्षणिक और सैन्य प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले 71 कैडेट्स को स्नातक उपाधियाँ दी गईं। कार्यक्रम में कैडेट्स के अभिभावक, संकाय और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौजूद रहे।

आईएमए के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल नगेंद्र सिंह ने विज्ञान संकाय के 30 और मानविकी संकाय के 41 कैडेट्स को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से संबद्ध स्नातक उपाधियाँ प्रदान कीं। ये कैडेट्स जनवरी 2026 से आईएमए में एक वर्ष के प्री–कमीशनिंग प्रशिक्षण के लिए अधिकारी कैडेट्स के रूप में शामिल होंगे।

बैठक

सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में देहरादून में पत्रकार कल्याण कोष और मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन समिति की बैठक आयोजित हुई।

समिति ने पत्रकार कल्याण कोष से पंद्रह दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों तथा गंभीर बीमारी से जूझ रहे दो पत्रकारों को उपचार के लिए पांच–पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की संस्तुति की।

मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत चार वरिष्ठ पत्रकारों को 8 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन देने की संस्तुति भी की गई।

सूचना महानिदेशक ने कहा कि राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप पत्रकारों के मामलों का संवेदनशीलता के साथ निस्तारण किया जा रहा है और संकट के समय अधिकतम सहायता का प्रयास किया जाता है।

समाचार पत्रों की सुर्खियों पर...

दैनिक वेतन संविदा कर्मियों की खबर को सभी समाचार पत्रों में स्थान मिला है। इस खबर पर दैनिक जागरण का शीर्षक है, संविदा कर्मियों को धामी सरकार का तोहफा पक्की होगी नौकरी। वहीं अमर उजाला में लिखा है दैनिक वेतन संविदा कर्मी होंगे नियमित अधिसूचना हुई जारी। आज से होने वाली पीसीएस मुख्य परीक्षा की गई स्थगित। अमर उजाला में छपी इस खबर के अनुसार एक सवाल को लेकर हाई कोर्ट की रोक के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने शनिवार से होने जा रही पीसीएस मुख्य परीक्षा 2025 की स्थगित कर दिया।